aware of the news item in Economic Times of 30.7.94 referred to here. The presentation made on behalf of the Chief Executives in the Conference of Chief Executives held on 30.7.94 raised certain issues which are summarised in the annexed Statement (see below). Dilution of Government stake below 50% in PSUs was not in the demand list.

Giving more autonomy to PSUs is an on going process. Government delegates more powers in respect of financial, personal and operational matters to the PSUs from time to time taking into consideration various changes/ developments in the industries economic environment.

(c) and (d) Rangarajan Committee Report is under examination of the Government. However, Government do not at present have any proposal to disinvest shares resulting in Government holding coming to below 51%.

Statement

1. It is time that public sector disinvested itself of activities which are best left to the private sector and public sector addresses itself to more crucial areas of development.

2. There is an urgent need to dispel the shadow of nonperformance of PSEs as a whole.

3. A conducive environment and autonomy in operations is needed.

4. There is a requirement of providing an environment in which the business and industry operate on the same ground rules notwithstanding the fact that the ownership is private or Government.

5. There is a need for higher autonomy and improved delegation to the public sector to enable them to operate and respond quickly in today's business environment.

6. The formation of joint ventures with foreign or domestic partners as a business strategy could be left to the Board.

7. Financial restructuring of public sector should be carried out on an enterprise wise financial analysis.

8. The sick and loss making cases are required to be decided quickly by BIFR within a laid down time frame.

9. The term of Chief Executives in effect should not be less than 5 years and there is also a need for filling up the Board level posts quickly.

PSUs in Rajasthan and Orissa

3170. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the total investment made till date in each of the public sector undertaking in Rajasthan and Orissa;

(b) what is the annual output of these undertakings and what are the details of profit or loss incurred by each of them, Statewise, during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 and so far upto 30th June, 1994;

(c) whether Government propose to handover any of these PSUs to private sector;

(d) whether any review by Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), of any Undertaking has been made so far, if so, with what results; and

(e) what are the details thereof, Statewise, and recommendations made by BIFR, if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) As on 31.3.1993 for which period only the information is available, there were six Central PSEs having their registered Office in each of the States of Rajasthan and Orissa. Name of these enterprises are given on page S-214 of Volume-I of P.E. Survey 1992-93 laid in the Parliament on 23.2.1994. Enterprisewise details of annual production for last three years are available in Statement No. 23A at pages S-134 to S-161 whereas enterprise wise details of net profit/loss during last five years are available in Statement 7A and 7 B at pages S-43 to S-50 in Volume-I of P.E. Survey 1992-93.

(c) Sir, Govt. have only disinvested some of its equity holdings in one enterprise from each of these States viz. HZL (Rajashtan), NALCO (Orissa).

(d) and (e) Schemes in respect of Instrumentation Ltd. in Rajasthan and Orissa

Drugs & Chemicals Ltd. in Orissa are under various stages of study by BIFR.

देश में सरकारी क्षेत्र के संस्थान

3171. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 के अंत में सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की संख्या 245 थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन संस्थानों द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ में गत वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान द्वारा शुद्ध लाभ की कितनी राशि अर्जित की गई;

(ङ) इन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और विदेशी ऋणों के रूप में प्राप्त पूंजी का प्रतिशत क्या था; और

(च) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन विदेशी ऋणों पर सरकार को कितना ब्याज देना पड़ा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार केवल जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, परिचालन में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उद्यम थे।

(ग) जी, हां। वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक इन उद्यमों द्वारा अर्जित कि गए लाभ की राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में उद्यमवार निवल लाभ का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड 1 के पृष्ठ विवरण 42 से 46 में दिया गया है जिसे 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

(ङ) से (च) सामान्य शेयर और ऋणों के रूप में निवेश, विदेशी ऋणों की राशि जिसमें ऐसे ऋणों पर ब्याज की राशि भी शामिल है का उद्यमवार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड III में तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते के सारांश में उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की दशा

3172. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग गत कई वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक उद्योग को कितना घाटा हुआ;

(घ) इन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में पूंजी निवेश की वर्ष-वार राशि क्या थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 से जून, 1994 तक अनेक कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो उन कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) 1992-93 के दौरान केवल जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 104 उद्यमों ने घाटा उठाया है। ऐसे उद्यमों के नाम पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके लाभ/हानि और सामान्य शेयर तथा ऋणों के रूप में निवेश का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-I के विवरण संख्या 7 ख और 16 में दिया गया है। जिसे दिनांक 23-2-1994 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ङ) से (छ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्य निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्य-निष्पादता में सुधार करने के लिए उद्यम विशेष के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित उद्यम द्वारा कार्रवाई की जाती है। किए गए कुछ उपाय हैं:- आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन योजना बनाना, वित्तीय, प्रबन्धकीय और संगठनात्मक पुनर्गठन करना, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि। खर्च की गई राशि किए गए उपाय की किस्म पर निर्भर करती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजित कार्यक्रम

3173. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने के